The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Jharkhand

Press Release

रांची
18/03/2021

इकफ़ाई विश्वविद्यालय में ग्रामीण भारत में समावेशी विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ

इकफ़ाई विश्वविद्यालय, झारखंड में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से ग्रामीण भारत में समावेशी विकास पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में सम्मानित अतिथियों में श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद, श्री परितोष उपाध्याय, मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ़), झारखंड सरकार, श्री आशीष कुमार पाढ़ी, मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), नाबार्ड, झारखंड सरकार और डॉ। रमेश मित्तल, निदेशक, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम), जयपुर से शामिल थे।

राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो ओआरएस राव ने कहा, "भारतीय अर्थव्यवस्था में कोविद-19 के दौरान कृषि के प्रति लचीलापन हाल ही में प्रदर्शित किया गया, जिसमें कृषि उत्पादन बाकी अर्थव्यवस्था के मुक़ाबले ऊपर चला गया था। पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एसएचजी और एफपीओ जैसी विकास संबंधी पहलों को बढ़ावा दिया है। हालांकि, इसकी कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हैं। प्रो राव ने कहा की सम्मेलन का उद्देश्य इसी मुद्दों पर चर्चा करना और उसी के समाधान पर पहुंचना है।

राष्ट्रीय संगोष्ठी में झारखंड के माननीय राज्यपाल श्रीमती द्रोपदी मुर्मू ने प्रतिभागियों को दिए अपने संदेश में कहा, "आत्मनिर्भर भारत का विचार सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से एक सहकारी समिति के रूप में स्वयं सहायता समूह बन जाएगा"।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्रीमती राधिका रस्तोगी ने भारत में एनडीएम और एसएचजी गठन की भूमिका पर प्रकाश डाला। आज, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में रहने की लागत पर सब्सिडी दे रहे हैं। एसएचजी में पोल्ट्री, डेयरी और अन्य कृषि संबद्ध क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न आय सृजन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस वजह से, मध्यस्थता की लागत कम हो गई है और ये क्षेत्र परिवर्तन से गुजर रहे हैं। उन्होने समझाया की महिला एसएचजी को बहुत कुशलता से प्रबंधित किया जा रहा है और बैंकों से बड़ी मात्रा में ऋण दिया जा रहा हैं, क्योंकि उनका शुद्ध एनपीए 2 प्रतिशत से कम है। श्रीमती रस्तोगी ने भारत के कई राज्यों से एसएचजी और एफ़पीओ की सफलता की कहानियां भी साझा कीं।

राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत में एफपीओ के ऐतिहासिक विकास को याद करते हुए, श्री आशीष कुमार पाधी ने बताया कि नाबार्ड का योगदान भारत में और विशेष रूप से झारखंड राज्य में एफपीओ की स्थापना और क्षमता का निर्माण किया गया है। श्री आशीष कुमार पाधी ने कहा की अब तक झारखंड में नाबार्ड द्वारा 158 एफपीओ स्थापित किए गए थे, जिनमें से अधिकांश व्यवहार्यता के चरण तक पहुंच गए थे और जल्द ही 32 और स्थापित किए जाएंगे।

श्री परितोष उपाध्याय ने एसएचजी के विकास के लिए सामाजिक गतिशीलता और क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। झारखंड राज्य में एसएचजी की स्थिति का वर्णन करते हुए, उन्होंने कहा कि वित्तीय साक्षरता और वित्तीय अनुशासन राज्य में एसएचजी आंदोलन की सफलता की कुंजी है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि एक क्लस्टर स्तर का दृष्टिकोण अपनाया जाए ताकि राज्य में अधिक परिवारों को लाभान्वित किया जा सके।

डॉ। रमेश मित्तल ने कहा कि बेहतर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के माध्यम से वैल्यू एडिशन एसएचजी और एफपीओ दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होना चाहिए। “माइनर वन उत्पादों, औषधीय और सुगंधित पौधों पर ध्यान केंद्रित करके, झारखंड को अपनी अनुकूल जलवायु परिस्थितियों और समृद्ध वन कवर का लाभ उठाने के लिए विशिष्ट रूप से उपयोग किया जा सकता है। प्रो अरविंद कुमार, रजिस्ट्रार और डॉ। भगत बारिक, अस्सस्ट डीन और सेमिनार समन्वयक ने भी इस अवसर पर बात की।

======